मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एनएचपीसी लिमिटेड और अन्य

799

(जयश्री ठाकुर जे.)

जयश्री ठाकुर के सामने , जे.

मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड-अपीलार्थी

बनाम

मेसर्स एन. एच. पी. सी. लिमिटेड और अन्य प्रतिवादीगण 2013 का एफ. ए. ओ. No.2702 और संबंधित मामले

12 अप्रैल, 2019

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996-**एस**. 34** और **37-**मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को केवल धारा **34** में बताए गए आधारों पर दरकिनार किया जा सकता है**-**रिकॉर्ड की पुष्टि करने और सभी प्रासंगिक सामग्री की जांच करने के बाद दिया गया निर्णय**-**जिला न्यायाधीश अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है**-**तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन**-**पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है**-**भले ही दो विचार संभव हों, मध्यस्थ द्वारा लिए गए विचार को तब तक दरकिनार नहीं किया जा सकता जब तक कि यह धारा **34** की शरारत के भीतर नहीं आता है**-**जिला न्यायाधीश का आदेश टिकाऊ नहीं है**-**अपील की अनुमति है।

यह माना गया कि एक बार मध्यस्थों ने अपना दिमाग लगा लिया था, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। अधिनियम की धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को अलग किया जा सकता है, यदि यह (ए) भारतीय कानून की मौलिक पुलिस के विपरीत है; (बी) भारत के हितों के विपरीत है; (सी) न्याय या नैतिकता के विपरीत है; या (डी) स्पष्ट रूप से अवैध है। सार्वजनिक नीति के विरोध में एक पुरस्कार आयोजित करने के लिए, पेटेंट अवैधता मामले की जड़ तक जानी चाहिए न कि एक तुच्छ अवैधता। हालांकि, एक पुरस्कार को रद्द किया जा सकता है यदि यह इतना अनुचित और अनुचित है कि यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है, तभी यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा।

(पैरा 17)

एम. के. घोष, अधिवक्ता

टीना गर्ग, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए।

रीता कोहली, राहुल के. शर्मा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता

उत्तरदाता No.1-NHPC के लिए।

जयश्री ठाकुर**,** जे।

(1) इस सामान्य आदेश के माध्यम से, यह अदालत उपरोक्त शीर्षक वाली 2013 की एफ. ए. ओ. No.2702,2013 की एफ. ए. ओ. No.2703 और 2014 की एफ. ए. ओ. No.9396 वाली सभी 800 में कानून के प्रश्नों के रूप में "मैसर्स ओमैक्स लिमिटेड बनाम मैसर्स एन. एच. पी. सी. लिमिटेड और अन्य" शीर्षक वाली तीन अपीलों का निर्णय करेगी।

उपर्युक्त अपीलें समान हैं। संक्षिप्तता के लिए तथ्यों को लिया जा रहा है

2013 के एफ**.** ए**.** ओ**. No.2702** से।

(2) एडिशनल द्वारा पारित दिनांकित 17.04.2013 आदेश के खिलाफ तत्काल अपील का निर्देश दिया गया है। जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद, जिसके द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 34 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आपत्तियों को अनुमति दी गई है और मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को दरकिनार कर दिया गया है, जबकि मामले को प्रभारी अभियंता को भी भेज दिया गया है।

(3) संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1 ने एन. एच. पी. सी. आवासीय परिसर, फरीदाबाद में टाइप 'ए' क्वार्टर (पैकेज-II) के बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण के लिए दिनांक 1 का अनुबंध/समझौता किया था। इस कार्य के लिए कुल 11,72,49,846/- का पुरस्कार दिया गया। कार्य शुरू होने की तिथि 11.02.2004 थी और पूरा होने की निर्धारित तिथि 10.03.2006 अर्थात 25 महीनों के भीतर थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से देरी के कारण, काम वास्तव में 06.07.2006 पर पूरा किया गया था, यानी परियोजना को पूरा करने में निर्धारित तिथि से 118 दिनों की देरी हुई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे, इसलिए अपीलार्थी ने 01.05.2008 दिनांकित पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 से एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त करने का आह्वान किया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति पर अपीलार्थी ने

अपने दावे का बयान दायर किया जिसे चुनौती दी गई।और उसके बाद 29.10.2010 पर एक पुरस्कार पारित किया गया।मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधिनियम की धारा 16 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें तर्क दिया गया था कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 55.1 के साथ पठित खंड 53 के प्रावधानों के अनुसार, खंड 7,8,10,13,17,18,21,23,24,29,32,33,34,37,38,39,40,41 और 44 के प्रभारी अभियंता द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम था और अपीलकर्ता पर बाध्यकारी था, और इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को इन खंडों के तहत आने वाले दावों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।मध्यस्थ न्यायाधिकरण समझौते के खंडों को देखने और पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय लेने आया कि चूंकि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 53 में यह प्रावधान है कि मुख्य अभियंता को अपना निर्णय लिखित रूप में देना है और चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए न्यायाधिकरण को दोनों पक्षों को सुनने के बाद उठाए गए दावों पर निर्णय लेना है।मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर रखी गई सामग्री को देखने के बाद, अपीलार्थी-ठेकेदार के दावों के कुछ हिस्से को अनुमति देते हुए 29.10.2010 पर एक विस्तृत और तर्कपूर्ण निर्णय पारित किया।उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने फरीदाबाद के जिला न्यायाधीश के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियां दायर कीं।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर आपत्तियाँ।प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर आपत्तियों का निपटान दिनांक 17.04.2013 के एक आदेश द्वारा किया गया था और दिनांकित 29.10.2010 के पुरस्कार को यह मानते हुए दरकिनार कर दिया गया था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के दावे पर निर्णय लेने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पक्षकारों को अपीलार्थी द्वारा दायर मध्यस्थता याचिका में उठाए गए विवादों पर निर्णय के लिए एन. एच. पी. सी., एन. एच. पी. सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33 फरीदाबाद के प्रभारी अभियंता के समक्ष 17.05.2013 पर उपस्थित होने और 17.05.2013 के 45 दिनों के भीतर दावे का निपटारा करने का निर्देश दिया।फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 17.04.2013 के आदेश के खिलाफ व्यथित होने के कारण, तत्काल अपील दायर की गई है।

(4) श्री एम. के. घोष, सुश्री टीना गर्ग के साथ अधिवक्ता, अपीलार्थी-मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड की ओर से पेश अधिवक्ता विद्वान वकील का तर्क है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा उठाए गए दावे खंड 53 या उसमें उल्लिखित किसी अन्य उपखंड के दायरे में नहीं आते हैं और मध्यस्थ न्यायाधिकरण पुरस्कार पारित करने के लिए सक्षम था।यह भी तर्क दिया जाता है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इस बात पर विचार करने में विफल रहे हैं कि अनुबंध की शर्त का उल्लंघन और नुकसान का आकलन करने का निर्णय और उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों की तरह दो अलग-अलग और अलग-अलग अवधारणाएं हैं और उल्लंघन का निर्णय केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता था और उस हद तक "अपवादात्मक वस्तुओं" को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पूर्वावलोकन से बाहर नहीं रखा गया था।यह भी बताया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को देखते हुए कि अपीलकर्ता अनुबंध को पूरा करने में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं था और इसका श्रेय प्रतिवादी संख्या 1 को दिया गया था, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने मामले को

निर्णय के लिए प्रभारी अभियंता को भेजने में गलती की।यह भी तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियों पर निर्णय लेते समय, न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तर्क में नहीं जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा की गई प्रस्तुतियों या निर्णयों में से किसी पर भी फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है या उन पर विचार नहीं किया गया है।एशियन टेक लिमिटेड बनाम में दिए गए निर्णयों पर निर्भरता रखते हुए

भारत संघ **1,** कलकत्ता बंदरगाह के लिए न्यासी मंडल बनाम इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज **2,** भारत ड्रिलिंग और फाउंडेशन ट्रीटमेंट

(पी) लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य 3 अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि खंड 39 के समान खंड केवल विभाग के लिए दावों पर विचार करने के लिए एक बाधा है, लेकिन मध्यस्थ को 1 (2009) 10 एससीसी 354 से प्रतिबंधित नहीं करता है।

दावों पर निर्णय लेना। दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए

जे. जी. इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ **4** में**,** के लिए विद्वान वकील

अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी नहीं है और मध्यस्थ द्वारा आगे की जांच के अधीन है।विद्वान वकील आगे नवोदय में दिए गए निर्णय पर निर्भर करते हैं।

मास एंटरटेनमेंट लिमिटेड बनाम जे. एम. 5 का संयोजन, यह तर्क देने के लिए कि एक बार

मध्यस्थ ने अपने समक्ष किसी मामले पर अपना दिमाग लगाया है, अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालत मामले का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती है जैसे कि यह एक अपील थी और भले ही दो विचार संभव हों, मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रबल होगा। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान वकील एल. आर. एस. द्वारा के. एन. सत्यपालन (मृत) में दिए गए निर्णय पर भी निर्भर करते हैं।

बनाम केरल राज्य और अन्य **6**।

(5) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल के शर्मा के साथ उपस्थित वरिष्ठ वकील सुश्री रीता कोहली का तर्क है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, पुरस्कार को दरकिनार करना उचित है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है। विद्वान वकील का तर्क है कि जहां पक्षों के बीच समझौते में कुछ दावों के संबंध में राहत देने के लिए एक विशिष्ट प्रतिबंध था, और मध्यस्थों द्वारा ऐसे दावों का निर्णय अधिकार क्षेत्र से अधिक था।विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि ठेकेदार को बिना जुर्माने के विस्तार दिया गया था और कीमत में वृद्धि की भी अनुमति दी गई थी और खंड 39.2 विशेष रूप से ठेकेदार द्वारा इस तरह की विस्तारित अवधि के लिए दावों को प्रतिबंधित करता है, जैसे कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत दावे मध्यस्थ नहीं थे। खंड 16 के अनुसार, ठेकेदार को निगम द्वारा देरी या सुविधा, सामग्री आदि प्रदान करने के मामले में प्रतिवादी संख्या 1 से कोई दावा करने या

हर्जाना मांगने से रोक दिया गया था और वह केवल खंड 39 के तहत समय के उपयुक्त विस्तार का हकदार होगा, जिसकी अनुमति दी गई थी। यह भी तर्क दिया जाता है कि दिनांकित 29.10.2010 (28.05.2011 पर संशोधित) पुरस्कार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि यह भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन था और इसने दिनांकित 20.02.2004 समझौते को भी ध्यान में नहीं रखा है। यह भी तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस तथ्य की अनदेखी की कि जोखिम नीति का अनुबंध लेना अपीलार्थी का काम था, लेकिन उसने आवश्यक काम नहीं किया था और यह प्रतिवादी संख्या 1 था जिसे काम करवाना था। यह इंगित किया गया है कि खंड 39.2 का उल्लंघन करते हुए मूल्य वृद्धि की भी गलत अनुमति दी गई थी। यह आगे बताया गया है कि खंड 53 के अनुसार, लिए गए निर्णय 4 (2011) 5 एस. सी. सी. 758

5 (2015) 5 एस. सी. सी. 698

6 (2007) 13 उच्चतम न्यायालय के मामले 43 एम/एस ओमैक्स लिमिटेड बनाम एम/एस एन. एच. पी. सी लिमिटेड और अन्य

803

(जयश्री ठाकुर जे.)

प्रभारी अभियंता द्वारा अंतिम होना था, इस प्रकार, अपीलार्थी को दिए गए सभी दावे अनुबंध के तहत विशेष रूप से वर्जित थे। उनकी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने निर्णयों पर भरोसा किया

भारत संघ बनाम मेसर्स वरिंदेरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड आदि में प्रस्तुत किया गया।7 , मेसर्स शर्मा एंड एसोसिएट्स कॉन्ट्रैक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। 8, रामकिशन सिंह बनाम रॉक्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड।9 .

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी बहुमूल्य सहायता से मामले की फाइल का अध्ययन किया है।

(7) तत्काल मामले में, पक्षों के बीच किए गए अनुबंध के बारे में कोई विवाद नहीं है या परियोजना को पूरा करने में 118 दिनों की देरी हुई है। अपीलार्थी ने इसमें 11 दावे किए, जिनमें से 7 को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई थी। इसमें अपीलार्थी ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अपने दावे दायर किए, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना लिखित बयान दाखिल करके विधिवत जवाब दिया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विवादित पुरस्कार पारित किया गया। निर्णय में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठाए गए प्रारंभिक मुद्दों का फैसला किया, जिसमें कहा गया था:-

‘‘प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए प्रारंभिक मुद्देः

1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 16 का नवाचार। इस संबंध में, प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अनुबंध के खंड 53 और 51 के प्रावधानों के अनुसार, खंड 7,8,10,13,17,18,21,23,24,29,32,33,34,37,38,39,40,41 और 44 के तहत लिए गए सभी निर्णय, प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और दावेदार पर बाध्यकारी है और इसलिए, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को दावेदार द्वारा उठाए गए दावों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

2. दावेदार ने तर्क दिया कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 53 और 55.1 में शामिल इन विवादों के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद के संबंध में प्रभारी अभियंता के निर्णय की कोई अंतिमता नहीं है। इसके अलावा, दावेदार द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कोई अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और मामले पर बहस करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसके अलावा, इन विवादों का एक अयोग्य संदर्भ मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अनुसार

7 2018(5) आर. सी. आर. (सिविल) 411

8 2017(5) एस. सी. सी. 743

9 2017(2) आर. ए. जे. 312 804

जी. सी. सी. का खंड 55 बनाया गया है और इसलिए, इन दावों पर न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता की जानी चाहिए। हमने पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमारा विचार है कि इस तरह के अपवादात्मक मामलों का निर्णय अनुबंध के चारों कोनों के भीतर किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर भी निर्णय लिया जाना चाहिए।जी. सी. सी. के खंड 53 में प्रावधान है कि ऐसा निर्णय लिखित रूप में दिया जाना है। चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए न्यायाधिकरण को दोनों पक्षों को सुनने के बाद उठाए गए दावों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना होगा।”

(8) इसके बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पक्षकारों और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच किए गए अनुबंध को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी के दावों पर एक-एक करके कारणों के साथ निर्णय लिया। (9) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कहाः

‘‘12. किसी भी पक्ष की ओर से भरोसा करने वाले किसी भी अधिकारी के साथ कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, प्रत्यर्थी

संख्या 1 के लिए एल. डी. वकील द्वारा भरोसा किए गए अधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। यह न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठा है, बल्कि यह न्यायालय इस सवाल पर गौर करने के लिए बाध्य है कि मध्यस्थों ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया था या नहीं। वर्तमान मामले में, मध्यस्थों की अधिकारिता को जी. सी. सी. के खंड 53 के तहत विशेष रूप से कम कर दिया गया था, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि खंड 7,8,10,13,17,18,21,23,24,29,32,33,34,37,38,39,40,41 और 44 से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होंगे और ठेकेदार पर बाध्यकारी होंगे। चूँकि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उठाए गए सभी दावे किसी न किसी प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, उनमें से कोई भी मध्यस्थता का विषय नहीं था। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विवादित पुरस्कार उन विवादों के संबंध में पारित किया गया है जिन पर विचार नहीं किया गया है और जो पक्षों के बीच अनुबंध की शर्तों के भीतर नहीं आते हैं। चूंकि अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है, इसलिए यह पुरस्कार निश्चित रूप से नैतिकता और नैतिकता का उल्लंघन है जो भारत की सार्वजनिक पुलिस का हिस्सा है। XXX XXX XXX।

14. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका की अनुमति दी जाती है और संशोधित मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एन. एच. पी. सी. लिमिटेड

28.05.2011 पर तुरंत अलग रखा जाता है। चूंकि इन मामलों का निर्णय प्रभारी अभियंता द्वारा किया जाना था, इसलिए पूरे रिकॉर्ड को कानून के अनुसार निपटान के लिए तुरंत प्रभारी अभियंता, एन. एच. पी. सी. को भेजने का आदेश दिया जाता है। दोनों पक्षों को, अपने वकील के माध्यम से, 17.5.2011 पर प्रभारी अभियंता के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है और प्रभारी अभियंता 45 दिनों की अवधि के भीतर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठाए गए विवादों का निपटारा करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

(10) पक्षकारों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले यह न्यायालय पक्षकारों के बीच किए गए अनुबंध के प्रासंगिक खंडों का उल्लेख करना चाहेगा, जो निम्नानुसार हैं:-

" खंड 53:अंतिमता खंड

अनुबंध के एक अविभाज्य भाग के रूप में यह स्वीकार किया जाएगा कि खंड संख्या 7,8,10,13,17,18,21,23,24,29,32,33,34,37,38,39,40,41 और 44 के तहत प्रभारी अभियंता द्वारा लिए गए सभी निर्णय और विशेष शर्तों में भी, जहां भी लागू हो, जो लिखित रूप में दिए जाएंगे, अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होंगे।

खंड **55:**मध्यस्थता

55.1 इसके अलावा, जैसा कि अन्यथा प्रावधान किया गया है, खंड 53 में इससे पहले, अनुबंध के संबंध में या उसके संबंध में ठेकेदार और निगम के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, विवाद या मतभेद, जिनमें निर्णय अंतिम और निर्णायक नहीं रहा है, को मध्यस्थता के लिए नीचे दिए गए तरीके से भेजा जाएगाः

कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे प्रश्न, विवाद या मतभेद के अस्तित्व के बारे में लिखित सूचना दे सकता है, जिसका निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार किया जाएगा।

XXX XXX XXX

खंड **39:**समाप्ति समय और विस्तार।

39.1 अनुसूची 'घ' या विस्तारित में निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए अनुमत समय, अर्थात पुरस्कार पत्र जारी होने की तारीख से पँचिश (25) कैलेंडर महीने (जुटाने के लिए एक (1) महीने की अवधि सहित)

समय, यदि कोई हो, इन शर्तों के अनुसार अनुबंध का सार होगा।

39.2 तथापि, यदि समग्र रूप से कार्य के निष्पादन में अनुसूची 'डी' में निर्दिष्ट समय से अधिक की देरी होती है,

i) खंड 18 के अनुसार अनुबंध के तहत किए जाने वाले काम की मात्रा में वृद्धि; या

(ii) खंड 35 के अनुसार कार्य का निलंबन; या

(ग) खंड 34 के अनुसार कार्य का पुनर्निर्माण; या

(iv) "फोर्स मैजेयूर" या

v) प्रभारी अभियंता के पूर्ण विवेकाधिकार में कोई अन्य खंड; फिर उपरोक्त जैसी कोई घटना होने के तुरंत बाद, ठेकेदार तदनुसार प्रभारी अभियंता को सूचित करेगा, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने और/या ठीक करने के लिए लगातार अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा और इस संबंध में जो भी आवश्यक हो वह करेगा।ठेकेदार लिखित रूप में समय बढ़ाने के लिए भी अनुरोध करेगा, जिसके लिए वह अनुबंध के तहत खुद को पात्र मान सकता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसी कोई भी घटना होने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर।

निगम द्वारा ऐसी विस्तारित अवधि के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।"

(11) एक प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी समझौते के खंड 39 के सामने अपने दावे

का हकदार होगा?अपीलार्थी ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजे और अतिरिक्त व्यय के रूप में विभिन्न नुकसानों के लिए दावा किया।यह आरोप लगाया गया था कि अनुबंध की प्रतिस्पर्धा में देरी प्रतिवादी संख्या 1 के कारण हुई थी, क्योंकि ड्राइंग जारी करने में देरी हुई थी, मुफ्त साइट उपलब्ध नहीं कराई गई थी, सीमेंट, स्टील आदि जारी करने के कारण देरी हुई थी और अन्य एजेंसियों द्वारा अन्य कार्यों की प्रतिस्पर्धा के कारण देरी हुई थी।मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया कि विलंब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया था और उस दावे को अनुमति दी जिसे समझौते के खंड 39 के विपरीत मानते हुए चुनौती दी गई थी।प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुबंध से परे नहीं जा सकता था और उसमें खंडों की अनदेखी कर सकता था, विशेष रूप से खंड 39, जो अनुबंध को पूरा करने के लिए आवश्यक समय प्रदान करता है और परियोजना को पूरा करने में देरी की स्थिति में, ठेकेदार केवल एक और शर्त के साथ समय में विस्तार का हकदार था कि कोई भी दावा मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एनएचपीसी लिमिटेड और अन्य नहीं होगा।

807

(जयश्री ठाकुर जे.)

इस तरह की विस्तारित अवधि के लिए मनोरंजन।दलीलों के समर्थन में, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भारत संघ पर भरोसा किया

बनाम मेसर्स वरिंदेरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड आदि।(ऊपर) जिसमें यह है

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी समझौते में यह निर्दिष्ट किया गया है कि स्थानीय कारकों और विनियमों के कारण कोई वृद्धि नहीं होगी, तो ठेकेदार का कोई दावा नहीं होगा और उसे काम के निष्पादन के दौरान न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान करना होगा।ऐसे खंड की उपस्थिति में, जिसके लिए ठेकेदार स्वेच्छा से सहमत था, किसी भी प्रस्थान की अनुमति नहीं दी जानी थी और ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी में किसी भी वृद्धि का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(12) बंदरगाह के लिए न्यासी मंडल के मामलों में इसी तरह का एक सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था

कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज (ऊपर); भारत ड्रिलिंग एंड फाउंडेशन ट्रीटमेंट (पी) लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य (ऊपर); एशियन टेक लिमिटेड बनाम भारत संघ (ऊपर)।पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स-डी-स्पेस के लिए न्यासी मंडल के मामले में -

आयु (ऊपर) उच्चतम न्यायालय ने अनुबंध में मध्यस्थ द्वारा इस तरह के प्रावधान के लिए ब्याज की अनुमति दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया;-"इस मामले में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उत्पन्न होता है और जिसे अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री साल्वे द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था, वह यह था कि मध्यस्थ ने विलंबित

भुगतान पर ब्याज के भुगतान के खिलाफ अनुबंध में निहित निषेध के बावजूद ब्याज को लंबित घोषित किया था।

इस संबंध में अनुबंध के खंड 13 (छ) पर भरोसा किया गया था और वह खंड निम्नानुसार हैः

आयुक्तों द्वारा किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में ब्याज के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा जो उनके और ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद के कारण उनके हाथ में हो सकता है या जो अंतरिम या अंतिम भुगतान करने में आयुक्तों की ओर से किसी भी देरी के संबंध में हो सकता है।

उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः- ''अतः संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या पूर्व में निकाले गए अनुबंध के खंड 13 के उपखंड (छ) को देखते हुए मध्यस्थ को अनुबंध के तहत ब्याज देने से प्रतिबंधित किया गया था। अब उपखंड (छ) में शब्द केवल आयुक्त को ब्याज के लिए किसी भी दावे पर विचार करने से रोकता है और मध्यस्थ को ब्याज देने से नहीं रोकता है।

ब्याज के लिए प्रारंभिक शब्द Rs.no दावे पर आयुक्त द्वारा विचार किया जाएगा 'यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि इरादा आयुक्त को ठेकेदार को भुगतान में देरी के कारण ब्याज देने से प्रतिबंधित करना था।खंड का कड़ाई से इस सरल कारण से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि जैसा कि संविधान पीठ ने इंगित किया है, आम तौर पर, एक व्यक्ति जिसके पास वैध दावा है, वह उचित समय के भीतर भुगतान का हकदार है और यदि भुगतान में उचित समय से अधिक देरी हुई है, तो वह वैध रूप से उस देरी के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, जो भी नाम उस ओर से उसके दावे को दिया जाए।यदि ऐसा है, तो हम उस अनुबंध की अवधि पर एक सख्त निर्माण करने के लिए उचित होंगे, जिस पर निर्भरता रखी गई है।कड़ाई से समझा जाए तो अनुबंध की अवधि केवल आयुक्त को विलंबित भुगतान के लिए ठेकेदार को ब्याज का भुगतान करने से रोकती है, लेकिन एक बार मामला मध्यस्थता में जाने के बाद मध्यस्थ के विवेक को किसी भी तरह से अनुबंध की इस अवधि से बाधित नहीं किया जाता है और मध्यस्थ को लंबित ब्याज अनुदान के प्रश्न पर विचार करने और ब्याज देने का अधिकार होगा यदि वह दावे को उचित समझता है।इसलिए, हमारी राय है कि अनुबंध के खंड के तहत मध्यस्थ को किसी भी तरह से बकाया ब्याज देने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था।''

(13) भारत ड्रिलिंग और फाउंडेशन उपचार के मामले में

(पी) लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य (ऊपर) उच्चतम न्यायालय ने फिर से इसी तरह के खंडों पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"3.इन सभी अपीलों में अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय इस तर्क पर आधारित किया है कि मध्यस्थ द्वारा जिन दावों की अनुमति दी गई थी, वे अनुबंध खंड 1.21 द्वारा वर्जित थे।इसके प्रासंगिक उपखंड इस प्रकार हैंः

1.21.1 किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान अनुबंध के पीडब्ल्यूडी फॉर्म एफ-2 के खंड 11 (ग्यारह) द्वारा दिया जाएगा।

1.21.2 निष्क्रिय श्रम, निष्क्रिय मशीनरी आदि के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.21.3 व्यावसायिक हानि या एहन कोनो हानिक लेल कोनो दावा स्वीकार नहि कयल जायत।

1.21.4 विभाग द्वारा निर्णय, ड्राइंग या विनिर्देशों को संप्रेषित करने में देरी के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग हालांकि काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाने पर विचार कर सकता है। यदि इसका कोई वास्तविक कारण है।

यदि यह संभव नहीं है, तो विभाग को काम के पुरस्कार पर पूरी साइट उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार को उसके अनुसार अपने कार्य कार्यक्रम की व्यवस्था करनी होगी। धीरे-धीरे स्थल देने के लिए कार्य के अधिनिर्णय पर स्थल नहीं देने के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, हालांकि मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए प्रभारी अभियंता के विवेक पर समय का उपयुक्त विस्तार किया जा सकता है।" (14) उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भरोसा करते हुए

पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज (ऊपर) और इस्पात एंग में दिया गया निर्णय। & फाउंड्री वर्क्स बनाम सेल 10 ने माना कि

एक तर्कपूर्ण निर्णय के साथ अदालत द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को बहाल कर दिया गया।

(15) इसी तरह, एशियन टेक लिमिटेड बनाम यूनियन के मामले में

भारत (ऊपर) सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया;-"13. इस संबंध में हम अनुबंध के खंड 70 का उल्लेख कर सकते हैं जो मध्यस्थता खंड है। उक्त खंड इस प्रकार हैः

70.मध्यस्थता अनुबंध के पक्षों के बीच सभी विवाद (उन लोगों के अलावा जिनके लिए सी. डब्ल्यू. ई. या किसी अन्य व्यक्ति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी व्यक्त किए गए अनुबंध द्वारा किया गया है), किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध के लिए लिखित सूचना के बाद उनमें से दूसरे को, निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले इंजीनियर कार्यालय के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

14. अनुबंध का खंड **11** इस प्रकार हैः

11. समय, विलंब और विस्तार (ए) समय अनुबंध का सार है और अनुबंध दस्तावेजों या प्रत्येक व्यक्तिगत कार्य आदेश में निर्दिष्ट किया गया है।

अनुबंध दिए जाने के बाद या कोई महत्वपूर्ण कार्य आदेश दिए जाने के बाद और उसके तहत काम करने से पहले जितनी जल्दी हो

जी. ई. शुरू हो गया है और ठेकेदार समय प्रगति चार्ट पर सहमत होगा।चार्ट अनुबंध दस्तावेजों या कार्य आदेश

में अलग-अलग मदों को पूरा करने के लिए बताए गए समय और/या समग्र रूप से अनुबंध या कार्य आदेश के सीधे संबंध में तैयार किया जाएगा।

(ख) यदि कार्यों में देरी हो रही हैः

(क) अनुसूची 13 में उल्लिखित सरकारी भंडारों की अनुपलब्धता के कारण; या

(ख) सरकार की अनुपलब्धता या टूटने के कारण। अनुसूची 'ग' में उल्लिखित उपकरण और संयंत्र, ऐसी किसी भी स्थिति में, इसमें पहले निहित प्रावधानों के बावजूद, जी. ई. अपने विवेक से समय का ऐसा विस्तार प्रदान कर सकता है जो उसे उचित लगे और ठेकेदार ऐसे विस्तारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।यदि ठेकेदार गैरीसन इंजीनियर द्वारा दिए गए विस्तार के लिए सहमत नहीं होता है, तो मामला स्वीकार करने वाले अधिकारी (या गैरीसन इंजीनियर द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध के मामले में सी. डब्ल्यू. ई.) को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ग) उपरोक्त शर्तों (क) और (ख) के तहत दिए गए विस्तार के परिणामस्वरूप, मुआवजे के संबंध में या अन्यथा, चाहे जो भी उत्पन्न हो, कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया; "18. उपरोक्त के अलावा, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है

पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज कि खंड **11** जैसा खंड केवल विभाग को दावे पर विचार करने से रोकता है**,** लेकिन यह मध्यस्थ को इस पर विचार करने से नहीं रोकता है।

इसके बाद भारत ड्रिलिंग में इस न्यायालय की एक और पीठ ने

& ट्रीटमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य।"

(16) एशियन टेक लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में**;** पोर्ट ऑफ कलकत्ता के लिए न्यासी मंडल बनाम इंजीनियर्स**-**डी**-**स्पेस**-**एज**;** भारत ड्रिलिंग एंड फाउंडेशन ट्रीटमेंट (पी) लिमिटेड बनाम

झारखंड राज्य (ऊपर), उच्चतम न्यायालय ने तत्काल मामले के समान खंडों में, जब एक ठेकेदार ने सामग्री की आपूर्ति में देरी आदि के कारण निर्धारित अवधि से अधिक किए गए अतिरिक्त काम/काम के लिए मुआवजे के लिए एक बिल उठाया था, यह देखा कि मध्यस्थ या अदालत इस सवाल पर विचार कर सकती है कि क्या दायित्व संतुष्ट हो गया है या नहीं।

तत्काल मामले में, खंड 39 (पूर्णता समय और विस्तार) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि 'निगम द्वारा ऐसी विस्तारित अवधि के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।'हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने पोर्ट ऑफ कलकत्ता के मामले

(उपरोक्त) में इसी तरह के खंड पर विचार करते हुए कहा है कि अनुबंध की अवधि केवल आयुक्त को विलंबित भुगतान के लिए ठेकेदार को ब्याज का भुगतान करने से रोकती है, लेकिन एक बार मामला मध्यस्थता में जाने के बाद, मध्यस्थ के विवेक को किसी भी तरह से अनुबंध की इस अवधि से दबाया नहीं जाता है और मध्यस्थ को अनुदान ब्याज के प्रश्न पर विचार करने और ब्याज देने का अधिकार होगा यदि वह दावे को उचित समझता है। उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को देखने के बाद, इस अदालत की यह सुविचारित राय है कि पक्षों के बीच किए गए समझौते में एक खंड यदि विभाग/निगम को दावों पर विचार करने से रोकता है, तो मध्यस्थों को काम पूरा करने में देरी के कारण ब्याज की अनुमति देने से नहीं रोका जाएगा, जिसके लिए प्रतिवादी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए विद्वान वकील द्वारा संबोधित तर्क टिकाऊ नहीं हैं।

(17) इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री रीता कोहली ने तर्क दिया कि खंड 53 विशेष रूप से कहता है कि अपवादित खंडों के तहत दावों पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता था और प्रभारी अभियंता द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। रिलायंस को मामले में रखा गया है।

मेसर्स शर्मा एंड एसोसिएट्स कॉन्ट्रैक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम प्रोग्रेसिव

कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड (उपर्युक्त) जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थता अनुबंध समझौते के संदर्भ में होनी चाहिए और जहां यह पाया जाता है कि मध्यस्थ द्वारा अनुबंध में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर दावे पर विचार किया गया था, मध्यस्थ का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विकृत होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मध्यस्थ पक्षों के बीच अनुबंध का एक प्राणी है और यदि वह अनुबंध की विशिष्ट शर्तों की अनदेखी करता है, तो यह अधिकार क्षेत्र की त्रुटि का सवाल होगा जिसे अदालत द्वारा ठीक किया जा सकता है।रिलायंस को रामकिशन सिंह के मामले में भी रखा गया है।

बनाम रॉक्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड & anr.(ऊपर) जहाँ यह आयोजित किया गया है

कि अधिनियम की धारा 28 (3) के तहत, मध्यस्थ पर अनुबंध की शर्तों और लेनदेन पर लागू व्यापार उपयोगों को ध्यान में रखने का दायित्व था और यदि मध्यस्थ धारा 28 (3) के अधिदेश का पालन नहीं करता है, तो विवादित पुरस्कार को बनाए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ है।

(18) जे. जी. इंजीनियर्स (पी.) मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष इसी तरह का प्रश्न विचार के लिए आने के बाद से यह मुद्दा अब समग्र नहीं है।

लिमिटेड बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) जिसमें पूछा गया प्रश्न निम्नानुसार था; -

"13. प्रतिवादीगण द्वारा भरोसा किए गए अनुबंध के खंड (2) और (3), निस्संदेह कुछ मामलों के संबंध में अधीक्षण अभियंता और प्रभारी अभियंता द्वारा अंतिम/अंतिम और बाध्यकारी/अंतिम और निर्णायक निर्णय लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या समझौते के खंड (2) और (3) में यह निर्धारित किया गया है कि निष्पादन में देरी और परिणामी उल्लंघन की जिम्मेदारी के संबंध में किसी भी प्राधिकरण का निर्णय अंतिम है और इसलिए उन मुद्दों को मध्यस्थता का विषय

होने से बाहर रखा गया है।"(19) उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की;" 22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थी कार्य के निष्पादन में देरी के लिए जिम्मेदार था या प्रतिवादीगण जिम्मेदार थे, मध्यस्थता योग्य था। मध्यस्थ ने उक्त मुद्दे की जांच की है और एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि कार्य के निष्पादन में देरी के लिए प्रतिवादीगण जिम्मेदार थे और ठेकेदार जिम्मेदार नहीं था। मध्यस्थ ने यह भी पाया कि प्रतिवादीगण उल्लंघन कर रहे थे और अनुबंध की समाप्ति अवैध थी।इसलिए, प्रतिवादीगण को परिसमापन हर्जाना लगाने का अधिकार नहीं था और न ही ठेकेदार से एक वैकल्पिक एजेंसी के माध्यम से काम पूरा करने में अतिरिक्त लागत (ऐसी अतिरिक्त लागत के संबंध में किसी भी वृद्धि सहित) का दावा करने का अधिकार था। इसलिए भले ही परिसमापन क्षति की दर के बारे में निर्णय और एक वैकल्पिक एजेंसी के माध्यम से काम पूरा करने में वास्तविक अतिरिक्त लागत के बारे में निर्णय, अपवादात्मक मामले थे, वे दावों 1,3 और 11 को तय करने के लिए प्रासंगिक नहीं थे, क्योंकि परिसमापन क्षति वसूलने या अतिरिक्त लागत का दावा करने का अधिकार केवल तभी उत्पन्न होगा जब ठेकेदार देरी के लिए जिम्मेदार था और उल्लंघन में था।

23. मध्यस्थ के इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं था और यह कि उत्तरदाता देरी के लिए जिम्मेदार थे, प्रतिवादीगण द्वारा परिसमापन हर्जाना लगाने या हर्जाने के रूप में काम पूरा करने में अतिरिक्त लागत का दावा करने का सवाल उत्पन्न नहीं होता है। एक बार जब यह माना जाता है कि ठेकेदार देरी के लिए जिम्मेदार नहीं था और देरी केवल प्रतिवादीगण की ओर से चूक और कमीशन के कारण हुई थी,

निम्नलिखित प्रावधान जो अधीक्षण अभियंता या प्रभारी अभियंता के निर्णय को अंतिम और निर्णायक बनाते हैं, अप्रासंगिक होंगे।इसलिए, मध्यस्थ के पास ठेकेदार के सभी दावों के साथ-साथ प्रतिवादीगण के दावों पर भी विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा। नतीजतन, मद 1,3 और 11 पर मध्यस्थ के निर्णय को बरकरार रखा जाना चाहिए और उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उन दावों के संबंध में निर्णय को अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि वे अपवादात्मक मामलों से संबंधित हैं, बनाए नहीं रखा जा सकता है।"

(20) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए विद्वान वकील का यह तर्क टिकाऊ नहीं है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थों ने अपीलार्थी के दावों का निर्णय लेते समय अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था।

(21) जैसा कि इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि खंड 39 का प्रतिबंध मध्यस्थों तक नहीं फैला होगा और मध्यस्थों ने अपीलार्थी के दावों का निर्णय लेते समय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया था, ऐसी परिस्थितियों में, निर्धारण के लिए जो अंतिम प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि मध्यस्थों ने एक बार पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर अपना दिमाग लगाया, तो क्या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का आदेश वैध है?इस संबंध में, नवोदय में उच्चतम न्यायालय की दोहरी पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है।

मास एंटरटेनमेंट लिमिटेड बनाम जे. एम. कम्बाइंस (ऊपर) जहाँ यह था

नीचे के रूप में देखा गया;-"8. हमारी राय में, न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। न्यायालय अभिलेख पर सामग्री का पुनर्मूल्यांकन करने और मध्यस्थ के दृष्टिकोण के स्थान पर अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित करने में उचित नहीं होगा। जहां अभिलेख के सामने कोई स्पष्ट त्रुटि है या मध्यस्थ ने वैधानिक कानूनी स्थिति का पालन नहीं किया है, तो और केवल तभी यह आयोग द्वारा प्रकाशित पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए उचित होगा।

मध्यस्थ। एक बार जब मध्यस्थ अपने सामने मामले पर अपना दिमाग लगा लेता है, तो न्यायालय मामले का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है जैसे कि यह एक अपील थी और भले ही दो विचार संभव हों, मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रबल होगा।

(देखिएःभारत कोकिंग कोल लिमिटेड VersusL.K। आहूजा, (2004) 5 एस. सी. सी. 109; रवींद्र एंड एसोसिएट्स बनाम भारत संघ, (2010) 1 एस. सी. सी. 80; मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (2010) 1 एस. सी. सी. 549; एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शन बनाम पवनहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, (2008) 16 एस. सी. सी. 128; और सतना स्टोन एंड लाइम

कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड एन. आर., (2008) 14 एस. सी. सी. "

(22) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्णय को देखने के बाद, इस अदालत का विचार है कि तत्काल मामले में तीन मध्यस्थों से युक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष रखी गई सभी प्रासंगिक सामग्री को देखा था और उसी को देखने के बाद, 11 दावों में से केवल 7 को ही अनुमति दी थी। एक बार जब मध्यस्थों ने अपना दिमाग लगा लिया था, तो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। अधिनियम की धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को अलग किया जा सकता है, अगर यह (ए) भारतीय कानून की मौलिक पुलिस के विपरीत है; (बी) भारत के हितों के विपरीत है; (सी) न्याय या नैतिकता के विपरीत है; या (डी) स्पष्ट रूप से अवैध है। सार्वजनिक नीति के विरोध में एक पुरस्कार आयोजित करने के लिए, पेटेंट अवैधता मामले की जड़ तक जानी चाहिए न कि एक तुच्छ अवैधता। हालाँकि, एक पुरस्कार को रद्द किया जा सकता है यदि यह इतना अनुचित और अनुचित है कि यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है, तभी यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा।

(23) हाथ में मामले में, मध्यस्थ का निर्णय निष्पक्ष और उचित है। दावा 1 (ए) के मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के रुपये के दावे के खिलाफ केवल रुपये की राशि की अनुमति दी। 25 लाख, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा ली गई नीति पर अपीलार्थी द्वारा प्राप्त लाभ में कटौती करते हुए। दावा संख्या 1 (बी) के संबंध में जो विविध कार्य के कारण की गई कटौती के आधार पर था; (i) विस्फोटक के कम उपयोग के लिए रु. 8,33,000 की वसूली के लिए; (ii) विविध खाते पर Rs.56,864/- की वसूली के लिए; (ii) Rs.40,325/- और Rs.37,102/- की वसूली के लिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलार्थी से ये वसूली सही तरीके से की

थी, इसलिए इन दावों को खारिज कर दिया गया था। रुपये 5,55,640 के दावे संख्या 3 के संबंध में-वृद्धि का भुगतान न करने के कारण, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड से सत्यापित करने के बाद, रुपये की अनुमति देने का फैसला किया। पर्याप्त मुआवजे के रूप में 4 लाख। दावे के संबंध में सं। 5 रु. से। 16,27,973-कार्य पूरा होने में देरी के कारण स्थल प्रतिष्ठान के कारण, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान पर अतिरिक्त राशि खर्च की गई, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उच्च पक्ष के दावे पर विचार करते हुए, रुपये के मुआवजे की अनुमति दी। लगभग 05 महीनों की कुल देरी के लिए 5,00,000- (यानी रु. 1,00,000-प्रति माह)। जहां तक देरी से पूरा होने के लिए निष्क्रिय उपकरणों और संयंत्रों आदि के कारण <ID1 की दावा संख्या 6,00,000/- का दावा है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दावा संख्या 5 के लिए दिए गए तर्क का जवाब देते हुए और टी एंड पी के प्रमुख हिस्से का उपयोग दावेदार द्वारा उसी परिसर में अन्य कार्यों के लिए एक साथ किया गया था। 1,00,000-प्रति माह यानी कुल रु।

5,00,000/- इस दावे के खिलाफ पुरस्कार दिया गया था। बैंक गारंटी आयोग पर अतिरिक्त व्यय के कारण नुकसान के लिए दावा संख्या 7 के संबंध में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कहा कि देरी आमतौर पर प्रतिवादी संख्या 1 के कारण होती है, जिसके लिए रु। इस दावे के खिलाफ 30,000/- की अनुमति दी गई थी। लाभ की हानि के लिए दावा संख्या 8 के संबंध में, मुख्य कार्यालय के खर्चों के कारण दावा संख्या 9 और अतिरिक्त साइट खर्चों के कारण दावा संख्या 1 के संबंध में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने यह देखते हुए कि दावेदार को दावा संख्या 5,6 और 7 के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया गया है, दावा संख्या 8 से 10 के खिलाफ आगे किसी मुआवजे की अनुमति नहीं दी गई थी। अंत में, दावे संख्या 2,4 और 11 के संबंध में, 27.07.2009 (यानी मध्यस्थता शुरू होने की तारीख से) से भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज की अनुमति दी गई थी। इन परिस्थितियों में, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक निष्पक्ष और उचित निर्णय पारित किया है और मध्यस्थों ने उठाए गए दावों पर विधिवत अपना दिमाग लगाया है और उसके बाद, उन्हें अनुमति दी गई या अस्वीकार कर दिया गया।इसलिए, विचाराधीन पुरस्कार को सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है और इस संबंध में निर्भरता को नवोदय मास एंटरटेनमेंट लिमिटेड बनाम जे. एम. कंबाइंस (सुप्रा) में दिए गए निर्णय पर रखा जा सकता है। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए मामले के कानून वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं।

(24) अपीलार्थी के वकील द्वारा एक अन्य तर्क दिया गया है कि फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है, क्योंकि अदालत के पास मामले को नए फैसले के लिए प्रभारी अभियंता को वापस भेजने की कोई शक्ति नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियों का फैसला करने वाली अदालत को उक्त धारा में निर्धारित मापदंडों के भीतर मामले का फैसला करना होता है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि किन्नरी में दिए गए एक फैसले में

मलिक और दूसरा बनाम घनश्याम दास दमानी 11 द सुप्रीम

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियों का फैसला करने वाली अदालत के पास मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वापस भेजने की शक्ति नहीं है और उक्त फैसले का पालन किया गया है।

राधा केमिकल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया **12.**

(25) प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील इस तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद नहीं करते हैं, लेकिन प्रस्तुत करते हैं कि इस अदालत को अपील पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए और मामले को नए सिरे से तय करने के लिए इसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को वापस भेज देना चाहिए।

(26) इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इस अदालत का विचार है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए प्रभारी अभियंता को वापस भेजने में गलती की है। किन्नरी में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय

मलिक और एक अन्य बनाम घनश्याम दास दमानी (ऊपर) और

राधा केमिकल्स बनाम भारत संघ (ऊपर) ने माना है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत, अदालत मामले को मध्यस्थ को वापस नहीं भेज सकती है।

(27) परिस्थितियों में, जब न्यायालय मध्यस्थ के निर्णय को दरकिनार कर देता है, पक्षकारों को नए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने से रोकता है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा क्योंकि 1996 का अधिनियम विवादों के त्वरित निपटारे के एकमात्र उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के तहत ही अपील का उपाय प्रदान किया गया है, जिसे धारा के तहत पुनः प्रस्तुत किया गया है; -

"37. अपील योग्य आदेश।–

(1) आदेश पारित करने वाले न्यायालय के मूल फरमानों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय को निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से अपील की जाएगी, अर्थात्:-

(ए) के तहत कोई उपाय देना या देने से इनकार करना।

धारा 9;

(ख) धारा 34 (2) के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को दरकिनार करना या दरकिनार करने से इनकार करना भी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अदालत में अपील होगी -

(क) उप-धारा में निर्दिष्ट याचिका को स्वीकार करना।

(2) धारा 16 की उप-धारा (3); या

(ख) धारा 17 के तहत अंतरिम उपाय देना या देने से इनकार करना।

इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश से कोई दूसरी अपील नहीं होगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को प्रभावित या छीन नहीं लेगा।"

(28) उक्त धारा के पढ़ने से पता चलता है कि धारा 9 के तहत कोई उपाय देने या देने से इनकार करने के आदेशों से अपील होगी; धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करना या अलग करने से इनकार करना।इस प्रकार, ऐसी स्थिति में जहां न्यायालय न्यायाधिकरण के निर्णय को दरकिनार करता है और साथ ही और अन्य को वापस भेजता है

नए सिरे से निर्णय के लिए मध्यस्थ, जो आदेश स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना है, इस अदालत की राय है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को दरकिनार करने वाले अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है और अपीलीय न्यायालय निर्णय की वैधता के संबंध में मुद्दे पर जाने के लिए सक्षम होगा।इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बनाम एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स

सीमित 13 जिसमें इसे निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है; "26. जैसा कि स्पष्ट है, पुरस्कार से दुखी व्यक्ति 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्ति दर्ज कर सकता है, और यदि उस पर पारित आदेश से व्यथित है, तो अपील कर सकता है।न्यायालय 1996 के अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार को रद्द कर सकता है या उससे निपट सकता है। यदि किसी सुधारात्मक उपाय के बारे में सोचा जाता है, तो इसे 1996 के अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि धारा 37 (1) किसी भी शिकायत के मामले में अपील के लिए निर्धारित करती है जिसमें अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करना शामिल है।

(29) इसलिए, उक्त निर्णय द्वारा समर्थित, इस न्यायालय को योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेना है।

(30) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलों की अनुमति दी जाती है।नतीजतन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और मध्यस्थ के पुरस्कारों को बरकरार रखा जाता है।

ऋतंभ्र ऋषि

13 (2017) 2 उच्चतम न्यायालय के मामले 37

अस्वीकरणीय :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

अंजू बाला

अनुवादक